प्रारंभिक परीक्षा

विश्व अमूर्त निवेश रिपोर्ट(WORLD INTANGIBLE INVESTMENT REPORT) 2026

संदर्भ

विश्व अमूर्त निवेश रिपोर्ट 2026 ने भारत को दुनिया की 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अमूर्त निवेश (intangible investments) में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में रेखांकित किया है, जो एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में इसकी स्थिति की पुष्टि करता है।

विश्व अमूर्त निवेश रिपोर्ट के बारे में

- **प्रकाशक**: विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) और लुइस बिजनेस स्कूल (इटली)।
- भारत ने दुनिया की 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अमूर्त निवेश में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की।
- 2008 के बाद से, वैश्विक अमूर्त निवेश मूर्त (tangible) निवेश की तुलना में तीन गुना अधिक तेजी से बढ़ा है और आर्थिक झटकों के दौरान अधिक लचीला (resilient) साबित हुआ है।
- कुल अमूर्त निवेश में संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है, जबकि अमूर्त निवेश गहनता (intensity) में स्वीडन सर्वोच्च स्थान पर है।
- भारत में सॉफ्टवेयर और डेटाबेस सबसे तेजी से बढ़ने वाली अमूर्त संपत्तियां हैं, जबकि संगठनात्मक पूंजी (organizational capital) और अनुसंधान व विकास (R&D) विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली श्रेणियां हैं।

ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स(GLOBAL LIVEABILITY INDEX) 2026

संदर्भ

दुनिया भर के शहरों में जीवन की गुणवत्ता का आकलन करते हुए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 जारी किया गया है।

ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के बारे में

- **प्रकाशक:** इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU)।
- **स्कोरिंग:** शहरों का मूल्यांकन 100-बिंदु पैमाने पर स्थिरता (25%), संस्कृति और पर्यावरण (25%), स्वास्थ्य देखभाल (20%), बुनियादी ढांचा (20%), और शिक्षा (10%) के आधार पर किया जाता है।
- ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में कोपेनहेगन, वियना और मेलबर्न को रहने योग्य शीर्ष तीन शहरों के रूप में स्थान दिया गया है। भारतीय शहरों में, नई दिल्ली 120वें स्थान पर है, उसके बाद मुंबई (121वें), चेन्नई (123वें) और बेंगलुरु (127वें) का स्थान है।

मोलस्क और डेजर्ट रेन फ्रॉग

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने चेतावनी दी है कि गहरे समुद्र में खनन (deep-sea mining) और हीरे के खनन के कारण क्रमशः मोलस्क और डेजर्ट रेन फ्रॉग (Desert Rain Frog) के विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है।

मोलस्क(Molluscs)

- मोलस्क अकशेरुकी (invertebrate) जानवर हैं (इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है)।
- सामान्य विशेषताओं में एक मेंटल (mantle), श्वसन और उत्सर्जन के लिए एक शरीर गुहा (body cavity), और एक तंत्रिका तंत्र शामिल हैं।
- **प्रमुख वर्ग (Major Classes)**
    - **सेफेलोपॉड (Cephalopods):** ऑक्टोपस, स्क्विड, कटलफिश, नॉटिलस, और विलुप्त अमोनाइट्स।
    - **गैस्ट्रोपॉड (Gastropods):** घोंघे (Snails) और स्लग (slugs)।
    - **बाइवाल्व (Bivalves):** क्लैम, सीप (oysters), मसल्स (mussels), और स्कैलप्स (scallops)।

डेजर्ट रेन फ्रॉग(Desert Rain Frog)

- बिल बनाने (burrowing) और अपना अधिकांश जीवन भूमिगत बिताने के लिए अनुकूलित एक फोसोरियल (fossorial) उभयचर (amphibian)।
- **आवास:** दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण-पश्चिमी नामीबिया के नामाक्वालैंड (Namaqualand) तट के साथ विरल वनस्पति वाले रेतीले तटीय टीले (dunes)।
- **IUCN रेड लिस्ट स्थिति:** सुभेद्य (Vulnerable)।

मगरमच्छ (MUGGER CROCODILE)

संदर्भ

हाल ही में, राजस्थान के कोटा जिले में चंद्रलोई नदी में कई मगरमच्छ मृत पाए गए, जिसका कारण एल्ड्रिन (Aldrin) नामक एक प्रतिबंधित ऑर्गेनोक्लोरिन कीटनाशक से विषाक्तता (poisoning) थी।

भारत में मगरमच्छों के बारे में

विशेषता	मगरमच्छ (Mugger Crocodile)	खारे पानी का मगरमच्छ (Saltwater Crocodile)	घड़ियाल (Gharial)
औसत आकार	4.5 मीटर तक	आमतौर पर 2.5–3 मीटर	7 मीटर तक
औसत वजन	लगभग 450 किग्रा	लगभग 1,000–1,500 किग्रा	लगभग 90 किग्रा
आवास	झीलों, नदियों, दलदलों और आर्द्रभूमियों सहित मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र। कुछ कृत्रिम जल निकायों और तटीय आर्द्रभूमियों में भी निवास करता है।	दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में तटीय क्षेत्र, मुहाने (estuaries), नदियाँ और दलदल (swamps)।	रेतीले किनारों वाली गहरी, तेज बहने वाली नदियाँ। वयस्क गहरे तालों (pools) पर कब्जा करते हैं, जबकि किशोर उथले, तेज पानी में रहते हैं।
भौगोलिक वितरण (वैश्विक स्तर पर)	भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और संभवतः बांग्लादेश तथा पूर्वी ईरान में	दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्से।	चंबल और गिरवा नदियाँ (भारत) और राप्ती-नारायणी नदी प्रणाली (नेपाल)।

	पाया जाता है।		
भौगोलिक वितरण (भारत)	गंगा बेसिन, बिहार, झारखंड, चंबल नदी और गुजरात।	पूर्वी तट के साथ, जिसमें भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान (ओडिशा), सुंदरबन, और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान।
IUCN रेड लिस्ट स्थिति	सुभेद्य (VU)	कम चिंताजनक (LC)	गंभीर रूप से लुप्तप्राय (CR)
CITES स्थिति	परिशिष्ट I	परिशिष्ट I	परिशिष्ट I
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	अनुसूची I	अनुसूची I	अनुसूची I

समृद्ध ग्राम (SAMRIDDH GRAM)

संदर्भ

दूरसंचार विभाग (DoT) ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure) के निर्माण में भारत की प्रगति को मान्यता देते हुए, अपनी प्रमुख 'समृद्ध ग्राम' पहल के लिए वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी (WSIS) पुरस्कार 2026 प्राप्त किया।

समृद्ध ग्राम के बारे में

- यह भारतनेट (BharatNet) नेटवर्क पर विकसित, दूरसंचार विभाग (DoT) का एक प्रमुख ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम है।
- **उद्देश्य:** ग्राम स्तर पर स्थापित समृद्धि केंद्रों के माध्यम से एकीकृत फिजिटल (फिजिकल + डिजिटल) सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना।
- भारतनेट भारत की प्रमुख ग्रामीण ब्रॉडबैंड पहल है जिसका उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे ग्रामीण-शहरी डिजिटल अंतर को पाटने में मदद मिलती है।

सायनोबैक्टीरिया (नीला-हरा शैवाल)

संदर्भ

आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया है कि सायनोबैक्टीरिया (नीले-हरे शैवाल) दूषित पानी से सीसा (lead) को प्रभावी ढंग से हटा सकते हैं, जो बायोरेमेडिएशन में उनकी क्षमता को उजागर करता है।

सायनोबैक्टीरिया (नीले-हरे शैवाल) के बारे में

- **सायनोबैक्टीरिया किंगडम मोनेरा (Kingdom Monera) से संबंधित प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक (photosynthetic prokaryotic) सूक्ष्मजीव हैं।**

- वे मीठे पानी, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और नम स्थलीय वातावरण में व्यापक रूप से वितरित हैं।
- एनाबीना (Anabaena) और नोस्टॉक (Nostoc) सहित कई प्रजातियों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर (fix) करने की क्षमता होती है, और इनका व्यापक रूप से जैव उर्वरक (biofertilisers) के रूप में उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से धान (चावल) की खेती में।
- मिट्टी की उर्वरता का समर्थन करने के अलावा, सायनोबैक्टीरिया को बायोरेमेडिएशन के लिए तेजी से खोजा जा रहा है, क्योंकि वे प्रदूषित पानी से जहरीली भारी धातुओं को अवशोषित करके निकाल सकते हैं।
- **बायोरेमेडिएशन (Bioremediation):** यह सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके प्रदूषकों को कम हानिकारक या गैर-विषाक्त पदार्थों में तोड़ने या बदलने की प्रक्रिया है, जिससे पर्यावरण संदूषण (contamination) कम होता है।

साइबर, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और आपूर्ति शृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया-भारत साझेदारी (PACTS)

संदर्भ

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और लचीली आपूर्ति शृंखलाओं में सहयोग को गहरा करने के लिए 'साइबर, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और आपूर्ति शृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया-भारत साझेदारी' (PACTS) पर हस्ताक्षर किए हैं।

PACTS के बारे में

- एक द्विपक्षीय ढांचा जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, महत्वपूर्ण आपूर्ति शृंखलाओं, साइबर लचीलापन और विश्वसनीय डिजिटल प्रौद्योगिकियों को मजबूत करना है।
- PACTS समझौता 'साइबर और साइबर-सक्षम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहयोग पर 2020 फ्रेमवर्क व्यवस्था' की जगह लेता है।
- **PACTS के पांच स्तंभ:** यह आपूर्ति शृंखला लचीलापन और विविधीकरण (महत्वपूर्ण खनिज और सेमीकंडक्टर), महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों (AI, अंतरिक्ष, दूरसंचार और जैव प्रौद्योगिकी), साइबर सुरक्षा, डिजिटल लचीलापन (इंडो-पैसिफिक में भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना), और रक्षा अनुसंधान सहयोग पर केंद्रित है।

कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM)

संदर्भ

भारत सरकार ने कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM) की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है।

कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM) के बारे में

- **मंत्रालय:** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।
- **प्रकार:** राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना।
- कृषि उत्पादकता बढ़ाने, श्रम के कष्ट (drudgery) को कम करने और खेती की लागत को कम करने के लिए समावेशी कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना।
- छोटे और सीमांत किसानों, महिला किसानों, एससी/एसटी किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और ग्रामीण उद्यमियों के लिए कृषि मशीनरी तक पहुंच में सुधार करना।
- **वित्तीय सहायता:**
    - प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सब्सिडी:

    - सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए 40%।
    - SC/ST किसानों, छोटे और सीमांत किसानों, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए 50%।
  - छोटे और सीमांत किसानों को CHC, FPO और SHG के माध्यम से ड्रोन-आधारित संचालन सहित यंत्रीकृत कृषि सेवाओं के लिए प्रति हेक्टेयर ₹2,000 मिलते हैं।

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र:** चयनित छोटी कृषि मशीनरी के लिए 100% तक की सब्सिडी और 'फार्म मशीनरी बैंकों' के लिए 95% वित्तीय सहायता सहित उन्नत सहायता प्रदान करता है।
- **महिला किसान:** योजना निधि का कम से कम 30% महिला लाभार्थियों के लिए निर्धारित (earmarked) है।
- **किसान ड्रोन:** वित्तीय सहायता प्रदान करके ड्रोन को अपनाने को बढ़ावा देता है, जिसमें ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs), और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के लिए प्रति ड्रोन ₹10 लाख तक और FPOs के लिए 75% अनुदान सहायता शामिल है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के बारे में

- **शुरुआत:** 2007
- **मंत्रालय:** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।
- **प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना।
- **उद्देश्य:** सार्वजनिक निवेश बढ़ाकर, उत्पादकता में सुधार, बुनियादी ढांचे को मजबूत करके और किसानों की आय में वृद्धि करके समग्र कृषि विकास को बढ़ावा देना।
- स्थानीय जरूरतों के आधार पर कृषि और संबद्ध क्षेत्र की परियोजनाओं को डिजाइन करने के लिए राज्यों को लचीलापन प्रदान करता है।
- कृषि यंत्रीकरण, मूल्यवर्धन, कृषि-नवाचार, कृषि-स्टार्टअप और कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करता है।

एएन/एफपीएस-115 पेव पॉज़ रडार प्रणाली (AN/FPS-115 PAVE PAWS RADAR SYSTEM)

संदर्भ

ताइवान का एएन/एफपीएस-115 पेव पॉज़ रडार प्रणाली दक्षिण चीन सागर के ऊपर चीन के हालिया बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण को ट्रैक करने में सहायक रहा, जो इसकी लंबी दूरी की मिसाइल का पता लगाने की क्षमताओं को उजागर करता है।

एएन/एफपीएस-115 पेव पॉज़ के बारे में

- यह एक अल्ट्रा हाई-फ्रीक्वेंसी (420–450 मेगाहर्ट्ज) फेज्ड-ऐरे (phased-array) रडार है जिसे मुख्य रूप से पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों (SLBMs) का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह प्रणाली एक अमेरिकी रक्षा ठेकेदार रेथियॉन (Raytheon) द्वारा विकसित की गई थी।
- बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा, यह विमानों, क्रूज मिसाइलों और समुद्री गतिविधियों की निगरानी कर सकता है।
- 3,000 समुद्री मील (लगभग 5,600 किमी) तक की दूरी पर 10 वर्ग मीटर रडार क्रॉस-सेक्शन वाले लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम।

फेज्ड-ऐरे (Phased-Array) तकनीक

- पारंपरिक यंत्रवत् घूमने वाले रडार के विपरीत, PAVE PAWS रडार रडार संरचना के बाहरी हिस्से पर लगे स्थिर फेज्ड-ऐरे एंटेना का उपयोग करता है।
- यह प्रेषित और प्राप्त संकेतों के चरण (phase) को समायोजित करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से रडार बीम को निर्देशित करता है, जिससे यांत्रिक गति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- यह बड़े क्षेत्रों में निरंतर निगरानी को सक्षम बनाता है और रडार को उच्च गति और सटीकता के साथ एक साथ कई लक्ष्यों का पता लगाने, ट्रैक करने और निगरानी करने की अनुमति देता है।

प्रतापगढ़ किला

संदर्भ

महाराष्ट्र सरकार ने प्रतापगढ़ किले की तलहटी में वीर जीवाजी महाले को समर्पित एक स्मारक के पहले चरण के लिए ₹1 करोड़ की मंजूरी दी है।

प्रतापगढ़ किले के बारे में

- **प्रतापगढ़ महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक पहाड़ी किला है।**
- **इस किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था, जिन्होंने इसके निर्माण की जिम्मेदारी अपने प्रधानमंत्री मोरोपंत पिंगले को सौंपी थी।**
- 1656 में बनकर तैयार हुआ यह किला नीरा और कोयना नदी घाटियों की रक्षा करने और पार दर्रे (Par Pass) को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था।
- **यह किला प्रतापगढ़ की लड़ाई (1659) के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जहां शिवाजी महाराज ने अफजल खान को हराया था, यह एक निर्णायक जीत थी जिसने दक्कन में मराठा शक्ति की स्थापना की।**
- प्रतापगढ़ की लड़ाई के दौरान, माना जाता है कि वीर जीवाजी महाले ने टकराव के दौरान अफजल खान के अंगरक्षक को मारकर शिवाजी महाराज की जान बचाई थी। लड़ाई के बाद, एक प्रहरीदुर्ग (watchtower) के रूप में अफजल बुरुज (Afzal Tower) का निर्माण किया गया था।
- इस लड़ाई ने बीजापुर सल्तनत के पतन को भी तेज कर दिया, जिसे बाद में 1686 में मुगलों द्वारा कब्जा कर लिया गया था।
- प्रतापगढ़ की लड़ाई (1659) में मराठा जीत की याद में हर 10 नवंबर को किले में शिव प्रताप दिन आयोजित किया जाता है।
- 1818 में, तीसरे आंग्ल-मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद यह किला ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया।
- किला ऊपरी किले और निचले किले के वर्गों में विभाजित है।
- **ऊपरी किले** में महादेव मंदिर सहित कई संरचनाएँ हैं।
- **निचले किले** में भवानी मंदिर है, जहाँ परंपरा के अनुसार, शिवाजी महाराज ने अपने अभियानों से पहले देवी भवानी का आशीर्वाद प्राप्त किया था।
- 30 नवंबर 1957 को मराठा शासक के सम्मान में जवाहरलाल नेहरू द्वारा शिवाजी महाराज की 17 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था।

मुख्य परीक्षा

भारत का आस्थगित (DEFERRED) भविष्य और जनसांख्यिकीय अवसर

संदर्भ

एक हालिया विश्लेषण ने चिंता जताई है कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) कम हो रहा है, जिससे पीढ़ी-दर-पीढ़ी मिलने वाले जनसांख्यिकीय अवसर के खोने का जोखिम है।

भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने में कैसे विफल हो रहा है?

- **अंतर-राज्यीय जनसांख्यिकीय भिन्नता (Divergence):** भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश कमजोर मानव पूंजी और रोजगार के अवसरों वाले उत्तरी राज्यों में तेजी से केंद्रित हो रहा है, जबकि दक्षिणी राज्यों की आबादी वृद्ध हो रही है।
    - **उदाहरण:** उत्तर प्रदेश और बिहार में युवा आबादी अधिक है, जबकि केरल और तमिलनाडु में वृद्धावस्था निर्भरता बढ़ रही है।
- **लगातार कौशल की कमी और उद्योग-अकादमिक जुड़ाव का अभाव:** शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योग की जरूरतों के बीच कमजोर तालमेल ने कार्यबल की रोजगार क्षमता (employability) और उत्पादकता को सीमित कर दिया है।
    - **उदाहरण:** भारत के कार्यबल के लगभग 3% ने ही औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- **निराश श्रमिक प्रभाव (Discouraged Worker Effect) और शिक्षित बेरोजगारी:** आधिकारिक बेरोजगारी दरें अक्सर 'निराश श्रमिकों' (जिन्होंने नौकरी खोजना बंद कर दिया है) को बाहर करके श्रम बाजार के संकट की वास्तविक सीमा को छिपा देती हैं। इसके अलावा, गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों की कमी के कारण शिक्षित युवाओं में भी बेरोजगारी बढ़ रही है, जो कमजोर रोजगार लोच (employment elasticity) और कौशल-कार्य बेमेल (skill-job mismatch) को दर्शाता है।
    - **उदाहरण:** भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि भारत के बेरोजगारों में युवाओं की हिस्सेदारी लगभग 83% है, और शैक्षिक प्राप्ति के साथ बेरोजगारी बढ़ रही है।
- **रुका हुआ संरचनात्मक परिवर्तन (Stalled Structural Transformation):** भारत ने पर्याप्त श्रम-गहन विनिर्माण (labour-intensive manufacturing) रोजगार उत्पन्न नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप रोजगारविहीन विकास (jobless growth), प्रच्छन्न (छुपी हुई) बेरोजगारी और अनौपचारिक काम का विस्तार हुआ है।
    - **उदाहरण:** ई-श्रम पोर्टल पर 30 करोड़ से अधिक कर्मचारी पंजीकृत हैं, जो अनौपचारिक रोजगार की प्रधानता को दर्शाता है।
- **महिला कार्यबल का कम उपयोग:** बढ़ती महिला श्रम-बल भागीदारी पर्याप्त औपचारिक और उत्पादक रोजगार में परिवर्तित नहीं हुई है, जिससे जनसांख्यिकीय लाभांश सीमित हो गया है।
    - **उदाहरण:** हाल ही के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आंकड़ों से महिला श्रम-बल की उच्च भागीदारी का पता चलता है, लेकिन यह वृद्धि नियमित वेतन वाले रोजगार के बजाय अवैतनिक पारिवारिक कार्य और स्वरोजगार में केंद्रित है।

भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने में शासन संबंधी और सामाजिक बाधाएं क्या हैं?

शासन संबंधी बाधाएं

- **सार्वजनिक क्षेत्र की आकांक्षाएं और खोए हुए उत्पादक वर्ष:** गुणवत्तापूर्ण निजी क्षेत्र की नौकरियों की कमी, विलंबित सार्वजनिक भर्ती के साथ मिलकर, लाखों युवाओं को लंबे समय तक परीक्षा की तैयारी में फंसा देती है, जिससे उनके उत्पादक वर्ष कम हो जाते हैं।
    - **उदाहरण:** प्रशासनिक देरी और मुकदमेबाजी के कारण केंद्र और राज्य सरकार की कई नौकरियों के लिए भर्ती 3-4 वर्षों तक खिंच जाती है।
- **सार्वजनिक व्यय में अदूरदर्शिता (Myopia):** अल्पकालिक राजनीतिक प्रोत्साहन अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और रोजगार सृजन में निरंतर निवेश के बजाय दृश्यमान (visible) घोषणाओं के पक्ष में होते हैं।
    - **उदाहरण:** कल्याणकारी और बुनियादी ढांचे की घोषणाओं पर अक्सर सार्वजनिक स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और व्यावसायिक संस्थानों में दीर्घकालिक निवेश की तुलना में अधिक राजनीतिक ध्यान दिया जाता है।
- **कमजोर मानव पूंजी निर्माण:** पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और मूलभूत शिक्षा (foundational learning) में लगातार कमी भविष्य के कार्यबल की संज्ञानात्मक (cognitive) और शारीरिक क्षमताओं को कम करती है, जिससे उत्पादकता और नवाचार सीमित हो जाता है।
    - **उदाहरण:** एनएफएचएस-5 (NFHS-5) (2019-21) की रिपोर्ट के अनुसार, पांच वर्ष से कम उम्र के 35.5% बच्चे अविकसित (stunted) हैं और 67.1% एनीमिक (एनीमिया से पीड़ित) हैं।

सामाजिक अड़चनें

- **श्रम का अनौपचारिकीकरण (Casualisation) और गिगिफिकेशन (Gigification):** गिग और संविदात्मक (contractual) कार्य के तेजी से विस्तार ने श्रम बाजार में लचीलापन बढ़ाया है लेकिन नौकरी की सुरक्षा, नियोक्ता-प्रायोजित कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा को कमजोर किया है।
    - **उदाहरण:** नीति आयोग की 'इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी (2022)' (India's Booming Gig and Platform Economy) रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत का गिग कार्यबल 7.7 मिलियन (2020-21) से बढ़कर 2029-30 तक 23.5 मिलियन हो जाएगा।
- **गरीबी का अंतर-पीढ़ी संचरण (Inter-generational Transmission):** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्थिर रोजगार तक सीमित पहुंच विशेष रूप से पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता (upward social mobility) को प्रतिबंधित करती है।
    - **उदाहरण:** वित्तीय बाधाएं अक्सर वंचित युवाओं को उच्च शिक्षा बंद करने या प्रतियोगी परीक्षाओं को छोड़ने के लिए मजबूर करती हैं।
- **आर्थिक भागीदारी में लैंगिक बाधाएं:** महिलाओं को अवैतनिक देखभाल जिम्मेदारियों, कार्यस्थल सुरक्षा चिंताओं और व्यावसायिक अलगाव के कारण उत्पादक रोजगार तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

आगे की राह

- **श्रम-गहन औद्योगीकरण को बढ़ावा देना:** रोजगार-लिंक्ड प्रोत्साहन (ELIs) के माध्यम से एमएसएमई (MSMEs) और श्रम-गहन क्षेत्रों को प्रोत्साहित करके पूंजी-गहन विकास से रोजगार-गहन विनिर्माण (employment-intensive manufacturing) की ओर स्थानांतरित होना।
    - **उदाहरण:** रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन (ELI) योजना के तहत कपड़ा, जूते, खाद्य प्रसंस्करण और इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना।

- **उद्योग-लिंक्ड कौशल विकास को मजबूत करना:** व्यावसायिक शिक्षा को उद्योग की मांग, अप्रेंटिसशिप और आजीवन सीखने (lifelong learning) के साथ एकीकृत करके 'स्किल इंडिया' और 'पीएमकेवीवाई' (PMKVY) में सुधार करना।
    - **उदाहरण:** रोजगार क्षमता में सुधार के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) का लाभ उठाना और जर्मनी के दोहरे (dual) अप्रेंटिसशिप मॉडल को अपनाना।
- **महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को अनलॉक करना:** गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार तक पहुंच बढ़ाने के लिए बच्चों की देखभाल, सुरक्षित परिवहन, लचीली कार्य व्यवस्था और महिला-गहन उद्योगों में निवेश का विस्तार करना।
    - **उदाहरण:** 'पालना' (Palna) के तहत सार्वजनिक क्रेच (crèches) को मजबूत करना, कार्यस्थल की सुरक्षा में सुधार करना, और कपड़ा व इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में महिलाओं के नेतृत्व वाले रोजगार को बढ़ावा देना।
- **नई अर्थव्यवस्था के लिए सामाजिक सुरक्षा मजबूत करना:** एक समर्पित कल्याण ढांचे (welfare architecture) के माध्यम से गिग और प्लेटफॉर्म वर्करों तक सामाजिक सुरक्षा, बीमा और कौशल विकास का विस्तार करना।
    - **उदाहरण:** सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को लागू करना और राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) अधिनियम, 2023 से सबक लेना।
- **परिणाम-उन्मुख शासन को संस्थागत बनाना:** सार्वजनिक निवेश पर अधिकतम प्रतिफल के लिए समयबद्ध भर्ती, परिणाम बजट (outcome budgeting), सामाजिक ऑडिट और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करना।
    - **उदाहरण:** केरल का 'पीपुल्स प्लान कैंपेन' (People's Plan Campaign) दर्शाता है कि विकेंद्रीकृत योजना और सामुदायिक निगरानी जवाबदेही में कैसे सुधार कर सकती है।
- **मानव पूंजी-उन्मुख कल्याण को बढ़ावा देना:** शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास परिणामों के साथ लाभों को जोड़कर दीर्घकालिक मानव पूंजी के निर्माण के लिए कल्याणकारी योजनाओं को फिर से डिजाइन करना।
    - **उदाहरण:** ब्राज़ील की 'बोल्सा फैमिलिया' (Bolsa Família) योजना अंतर-पीढ़ीगत गरीबी को तोड़ने के लिए स्कूल में उपस्थिति और स्वास्थ्य जांच से जुड़े सशर्त नकद हस्तांतरण (Conditional Cash Transfers - CCTs) का उपयोग करती है।